

## Inauguration of Online Issue / Return of books through e-Granthalaya ver.4 at District Library Raibarailly (UP) and launching of Membership Card

At District Library Raibarailly (UP) on 16<sup>th</sup> May 2016 **Principal Secretary Secondary Education, Shri Jitendra Kumar** Launched “**Membership Card**” for Issue Return of Books using online version of e-Granthalaya version 4, a Library Management Software developed by NIC. **e-Granthalaya** has been adopted for computerization of in-house activities of at all 71 District Public libraries of Uttar Pradesh. **Mr. Arvind Mishra**, Senior System Analyst gave a presentation of Issue / Return of Books using Barcode through e-Granthalaya to Users, Guests and children present using their Membership Card. This membership card has barcode and is valid for using at any of the District Public Library of Uttar Pradesh for issuing books.

आदर्शता 60 (अधि.) 12 (न्यून.)

# एक क्लिक पर पुस्तकालय हाजिर

**नई पहल**

- प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने की ऑनलाइन पुस्तकालय की टेस्ट लांचिंग



जागरण संवाददाता, रायबरेली: उत्तर प्रदेश के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय को किस रैंक में कौन की पुस्तक कहाँ पर रखी है। इसका ब्योरा आप अब घर बैठे जुटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको राजकीय पुस्तकालय का सदस्य बनाना होगा। इस हाईटेक तकनीकी व्यवस्था की टेस्ट लांचिंग प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने किया। पुस्तकालय विभाग की ओएसडी सांत्वना तिवारी ने ऑनलाइन पुस्तकालय की खूबियों के विषय में राजकीय पुस्तकालय के सदस्यों को बताया।

माध्यमिक शिक्षा सचिव जितेंद्र कुमार ने ऑनलाइन पुस्तकालय की टेस्ट लांचिंग के दौरान कहा कि पुस्तकालय के प्रति पाठकों का रुझान बढ़ाने एवं उन्हें कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से आधुनिक पुस्तकालय प्रदान की जा सकेगी। प्रदेश भर में ऑनलाइन योजना का शुभारंभ शीघ्र ही मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। 10वीं व 12वीं के छात्रों को शासन द्वारा लैपटॉप दिए गए हैं उनके लैपटॉप पर पुस्तकालयों का लिंग उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे वे भी पुस्तकालय से जुड़ सकें। पुस्तकालय विभाग की ओएसडी सांत्वना तिवारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी योजना के अंतर्गत राजकीय जिला पुस्तकालय को एनआइसी द्वारा विकसित किया गया है। इसमें पुस्तकों का ब्योरा कंप्यूटर पर ऑनलाइन रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। एनआइसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक अरविंद सिंह ने बताया कि ई-ग्रंथालय के माध्यम से डिजिटाइज्ड करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। डीआईओएस विनय मोहन ने कहा कि पुस्तकें ईमान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। पुस्तकालय इंचार्ज उत्कर्ष सिंह ने बताया कि इस योजना के विस्तार से पुस्तकालय में सदस्यों की संख्या में इजाफा होगा। मुकुल कुमार, डॉ विवेकानंद त्रिपाठी, राजवंत सिंह, सुनील यादव समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे।

**प्रमुख सचिव ने किया सम्मानित**

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयनित किए गए गाइड्स, रेजर व स्काउट को सम्मानित किया। इसमें एनएसपीएस की मिताली गुप्ता, मोनिका गुप्ता, शालिनी गुप्ता, आकांक्षा व नेहा पटेल रेजर में दयानंद पीजी कॉलेज, बछरावाँ की वैशाली गुप्ता व प्रियंका चौधरी, एफजी कॉलेज की उमा पटेल, स्काउट्स में एनएसपीएस के निखिल तिवारी, अवधराज व आशीष बाजपेयी, जीआइसी के अरविंद, शुभम सोनी, रंजनीश पाल, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगागंज के शिखर शुक्ला व पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकअहमदपुर के मोहन मतीन, प्रकाश व सतीश सोनकर, स्काउट भवन से शिवेंद्र पटेल को अवार्ड दिया। डॉ नीलिमा श्रीवास्तव, प्रतिभा शुक्ला, रंजना यादव, दीपा मोर्या, प्रतिभा पाल, सुमित्रा यादव, पवन कुमार मोर्या, जितेंद्र सिंह, देवेन्द्र बाजपेयी को स्काउट मास्टर व गाइड कैप्टन का हिमालय उडबैज का पार्वर्षित भी प्रदान किया। लीडर ट्रेनर लक्ष्मीकांत शुक्ला, साधना शर्मा, निरुपमा बाजपेयी, शिवशरण सिंह समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे।

**शुभारंभ करते प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार**

का रुझान बढ़ाने एवं उन्हें कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से आधुनिक पुस्तकालय प्रदान की जा सकेगी। प्रदेश भर में ऑनलाइन योजना का शुभारंभ शीघ्र ही मुख्यमंत्री द्वारा





## प्रदेश के राजकीय पुस्तकालय हाईटेक

■ रायबरेली।

सहारा न्यूज ब्यूरो

राजकीय जिला पुस्तकालयों के माध्यम से उपर से विभिन्न पुस्तकों का आदान-प्रदान ई ईसू एण्ड रिखीव सिस्टम से करने के लिए प्रदेश के प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेन्द्र कुमार ने योजना का शुभारम्भ किया।

जिला पुस्तकालय रायबरेली के सभागार में पाठकों को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव शिक्षा जितेन्द्र कुमार ने कहा कि प्रदेश के 71 जिलों में एनआईसी के माध्यम से पाठकों का ई ईसू एण्ड रिखीव सिस्टम से आदान-प्रदान देखा जा सके है। आजीवन कार्ड होने से पाठकों को विशेष सुविधा रहेगी। पाठकों के सवालों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जून 2016 तक सभी राजकीय विद्यालयों के शिक्षक के पद भर दिये जाएंगे और जल्द से जल्द राजकीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाने का पूरा प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि हर जिले में कनिष्ठ स्कूल और स्कूल की योजना में प्रतिवर्ष 100 विद्यालयों को 50 लाख रुपये शैक्षिक संशोधन के लिए दिये जा रहे हैं। स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर चलाया जाएगा। प्रतिभावान मेरिट के

इन्टरनेट के माध्यम से पुस्तकों का होगा आदान प्रदान।



दीर्घ प्रउजडललत कर उदकडन कडले प्रमुख सचिव शिक्षा जितेन्द्र कुमार। फोटो - सहारा न्यूज

बच्चों को लैपटॉप दिये जाएंगे। उन्होंने रायबरेली की तीन छात्राओं को हार्डस्कूल को मेरिट में स्थान पाने पर बधाई दी। प्रमुख सचिव शिक्षा ने राजकीय हार्डस्कूल सिलहुर के प्रधानाचार्य शिव नारायण सोनी, देवेन्द्र कुमार, डा. संतलाल विश्वकर्मा, आकांक्षा सिंह, विनय मोहन वन को पाठक परिचय

पत्र हस्तगत करके लोगों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभिप्रेरित किया। सभागार में पुस्तकालय प्रकौश्ट ओएसडी सार्वजनिक विद्यालय जितेन्द्र विनय मोहन वन, परिचयेश कुमार, अरवि श्रीबाबू, सार्वजनिक शिक्षण, पुस्तकालयपालक उत्कर्ष सिंह समेत तथाप लोग उपस्थित रहे।

# 15000 लैपटाप पर होगा लाइब्रेरी का लिंक

रायबरेली | हिन्दुस्तान संवाद

राजकीय जिला पुस्तकालय में आयोजित समारोह में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने ई-लाइब्रेरी, पुस्तकों के आनलाइन इश्यू और डिजिटल सदस्यता कार्ड सुविधा की टेस्ट लांचिंग की। इस मौके पर उन्होंने नए सदस्यों को डिजिटल सदस्यता कार्ड का वितरण भी किया।

उन्होंने कहा कि इस सेवा के शुरू होने के बाद कोई भी सदस्य घर बैठे पुस्तकों की पुस्तकालय में उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। वह अपने निकटतम राजकीय जिला पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकेगा। सदस्यों को दिया जा रहा डिजिटल कार्ड प्रदेश के सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों में मान्य होगा। जल्दी ही प्रदेश स्तर पर इस सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री से कराया जाएगा।

इसके लिए उन्हें राजकीय पुस्तकालय जाकर सदस्य बनना होगा। उन्हें लाग इन और पासवर्ड दे दिया जाएगा। जिनके पास इंटरनेट नहीं है वे अपने लैपटाप के साथ लाइब्रेरी में आकर वहां उपलब्ध निःशुल्क वाई-फाई से



डिजिटल सदस्यता कार्ड प्रदान करते प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार • हिन्दुस्तान

## हर जिले में होंगे 'क्लीन ग्रीन' स्कूल

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि सरकारी माध्यमिक स्कूलों की सूरत बदली जाएगी। हर साल प्रदेश में 100 क्लीन ग्रीन स्कूल संचालित होंगे। रायबरेली में जीआईसी और जीजीआईसी को चुना गया है। यहां बच्चों के लिए आर ओ और चिल्ड वाटर होगा। पांच किलोवाट का सोलर जेनरेटर होगा। स्मार्ट क्लास संचालित होंगे।

कनेक्ट होकर आन-आइन पुस्तकें पढ़ सकेंगे। वहीं हुए राष्ट्रपति अवार्ड एवं पाचमिंट वितरण समारोह में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने वर्ष 2015 में राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयनित गाइड्स, रेंजर व

स्काउट को अवार्ड प्रदान किया। इस मौके पर ओएसडी पुस्तकालय शांत्वना तिवारी, डीआईओएस विनय मोहन वन, एनआईसी के वैज्ञानिक अरविंद मिश्र, उत्कर्ष सिंह आदि थे।

# राजकीय पुस्तकालयों से अब ऑनलाइन मिलेंगी पुस्तकें

रायबरेली (ब्यूरो)। राजकीय पुस्तकालयों ने ऑनलाइन पुस्तकें लेने व सदस्य बनने के लिए सोमवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने ई-लाइब्रेरी की टेस्ट लांचिंग की। उन्होंने कहा कि एनआईसी के माध्यम से प्रदेश के 71 जिले ई-लाइब्रेरी से जुड़ गए हैं। सदस्यता ग्रहण करके ई-कार्ड हासिल करने वाले सदस्य ऑनलाइन किताबें व जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में 70 हजार से अधिक पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकों को ऑनलाइन कराने का काम चल रहा है।

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार, डीआईओएस डॉ. विनय मोहन, प्रधानाचार्य शिवनारायण सोनी, देवेन्द्र कुमार, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव सदस्य बनें। सभी को ई-कार्ड दिया गया।



रायबरेली में सोमवार को राजकीय पुस्तकालय में ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ करते प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार।

प्रमुख सचिव ने पुस्तकालय में ई-लाइब्रेरी की टेस्ट लांचिंग

प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश में इस चार टॉपों को मिलने वाले लैपटॉप में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। लैपटॉप में पुस्तकालयों को लिंक रखा जाएगा। इसके लिए मैजैस की सुविधा भी दी जाएगी। इस मौके पर विशेष कार्याधिकारी पुस्तकालय शांत्वना तिवारी, विवेकानंद त्रिपाठी, अरविंद, उत्कर्ष आदि मौजूद रहे।

## जून में शिक्षकों की भर्ती

प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने बातचीत में कहा कि राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण बेहतर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसलिए जून में शिक्षकों की भर्ती करके इस कमी को दूर कराया जाएगा। एक जुलाई से शुरू होने वाले शिक्षासत्र में राजकीय स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि राजकीय स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। सीबीएसई पैटर्न पर मंडल स्तर पर एक-एक स्कूल खोलकर पढ़ाई शुरू कराई गई है। 200 स्कूलों को क्लीन ग्रीन बनाया जाएगा।

